भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2795
बुधवार, 17 जुलाई, 2019/26 आषाढ़, 1941 (शक)

बेरोजगारी की बदलती प्रवृत्ति

2795. श्री संजय सिंहः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बेरोजगारी दरों का राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) अल्पविकसित राज्यों जैसे पश्चिमी बंगाल की तुलना में पूर्ण विकसित राज्यों जैसे दिल्ली, तमिलनाडु में बेरोजगारी दरों के कम होने के क्या कारण हैं;
(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
(घ) राज्य सरकारों के सहयोग से बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क एवं ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर अनुमानित बेरोजगारी की दर 6.0% थी। दिल्ली एवं तमिलनाडु में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर पश्चिम बंगाल के 4.6% की तुलना में क्रमशः 9.4% एवं 7.5% है। इसका राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग एवं घ): नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने, पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार, सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु ईपीएफ एवं ईपीएस के लिए 3 वर्षों हेतु नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत लघु/सूक्ष्म व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

सरकार ने राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) परियोजना को कार्यान्वित किया है, जिसमें एक ऐसा डिजिटल पोर्टल शामिल है जो गतिशील, दक्ष एवं सकारात्मक ढंग से योग्यता अनुरूप रोजगार हेतु रोजगार चाहने वालों एवं नियोक्ताओं के लिए एक राष्ट्र-व्यापी ऑनलाइन मंच प्रदान करता है तथा इसमें रोजगार चाहने वालों हेतु आजीविका संबंधी विषय-वस्तु का भंडार है।

स्टार्ट-अप इंडिया भारत सरकार की एक फ्लैगशीप पहल है। यह एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करना चाहती है, जो व्यापार आरंभ करने को संवर्द्धित करने, धारणीय आर्थिक विकास को प्रेरित करने तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर को सृजित करने में सहायक है।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास तथा औद्योगिक गलियारे जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने की संभावना है। युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने तथा नियोजन की सुविधा प्रदान करने के लिए मंत्रालय/विभाग/राज्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास योजनाएं चलाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एनएपीएस) जैसी योजनाएं, जिनमें सरकार शिक्षुओं को देय वृत्तिका के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है, भी रोजगार प्राप्त करवाने हेतु युवाओं की नियोजनीयता को बढ़ाती हैं।

*****

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 17.07.2019 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2795 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2017-18 (पीएलएफएस) के दौरान सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर 15 एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की बेरोजगारी दर के राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	बेरोजगारी दर (% में)
1.	आंध्र प्रदेश	4.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.8
3.	असम	7.9
4.	बिहार	7.0
5.	छत्तीसगढ़	3.3
6.	**दिल्ली**	**9.4**
7.	गोवा	13.9
8.	गुजरात	4.8
9.	हरियाणा	8.4
10.	हिमाचल प्रदेश	5.5
11.	जम्मू और कश्मीर	5.4
12.	झारखंड	7.5
13.	कर्नाटक	4.8
14.	केरल	11.4
15.	मध्य प्रदेश	4.3
16.	महाराष्ट्र	4.8
17.	मणिपुर	11.5
18.	मेघालय	1.6
19.	मिजोरम	10.1
20.	नागालैंड	21.4
21.	ओडिशा	7.1
22.	पंजाब	7.7
23.	राजस्थान	5.0
24.	सिक्किम	3.5
25.	**तमिलनाडु**	**7.5**
26.	तेलंगाना	7.6
27.	त्रिपुरा	6.8
28.	उत्तराखंड	7.6
29.	उत्तर प्रदेश	6.2
30.	**पश्चिम बंगाल**	**4.6**
31.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	15.8
32.	चंडीगढ़	9.0
33.	दादर और नगर	0.4
34.	दमन और दीव	3.1
35.	लक्षद्वीप	21.3
36.	पुडुचेरी	10.3
	अखिल भारत	6.0

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), 2017-18, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय